



प्रगति पथ पर गतिमान राजस्थान



शहरी विकास को नई रफ्तार - आधुनिक राजस्थान की नई पहचान

मजबूत सड़कें • सुगम यातायात • बेहतर ड्रेनेज • आधुनिक सीवरेंज • सुरक्षित सबवे • बेहतर मेडिकल सुविधाएं • श्रमिक कल्याण • स्वच्छ एवं हरित परिवहन

राजस्थान के शहरों को मिल रही ₹2,340 करोड़ की सौगातें 941 कार्यों का शिलान्यास-लोकार्पण

श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के
1 लाख 32 हजार 421 लाभार्थियों को ₹154 करोड़ से अधिक की सहायता राशि की डीबीटी

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में जयपुर को बड़ी सौगात

लोकार्पण

RUHS जयपुर : 128-स्लाइस CT स्कैन मशीन

जनाना चिकित्सालय, चांदपोल : नवीन आईपीडी टावर

SMS अस्पताल :

आयुष्मान टावर अंतर्गत कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज संस्थान

RUHS जयपुर :

1.5 टेस्ला MRI मशीन तथा नवीन स्नातक छात्रावास

जयपुर जिले में झोटवाड़ा के अभयपुरा के उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं दूदू विधानसभा क्षेत्र के उप स्वा. केन्द्र, रेहलाना का निर्माण कार्य

शिलान्यास

जयपुर जिले के झोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय

पीएम ई-बस योजना

71 ई-बसों का शुभारंभ

जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से
तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर से 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ

वंदे मातरम् का गायन राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक मुद्दा बनता जा रहा है

भाजपा इस बात को बड़े ध्यान से देख रही है कि कानून पास होने के बाद किसी भी स्तर पर वंदे मातरम् की अवहेलना तो नहीं हो रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता क्या अमित शाह हताश हैं या उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ रुक जाना चाहिए? या फिर वे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके अपना खोया हुआ राजनीतिक प्रभाव वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कहानी 1897 से शुरू होती है, जब कांग्रेस के एक अधिवेशन में पूरा वंदे मातरम् बिना किसी झिझक या समस्या के गाया गया था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। 1930 के दशक में, जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन की और तेज कर दिया था, तब कुछ नेताओं ने वंदे मातरम् के तीसरे अंतरे पर आपत्ति जतानी शुरू की। इस अंतरे में मूर्ति पूजा का वर्णन था, जिसे इस्लाम धर्म में मान्यता नहीं है। इस विवाद को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उन्होंने पूरे विवाद का

- कांग्रेस ने भी मान लिया है, जैसा राहुल गांधी ने भी कहा है, कि कानून बनने के बाद वंदे मातरम् को पूरा गाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, फिर भी थोड़ी बेचैनी सी है।
- सवाल यह है कि क्या वंदे मातरम् चुनावी मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस मुसलमानों की सहानुभूति पाना चाहती है, वहीं भाजपा इस मुद्दे पर हिंदू वोटों का धुवीकरण करना चाहती है और वंदे मातरम् के संदर्भ में विपक्षी दलों की मामूली सी चूक को भी हवा दे रही है।
- इसी संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर वंदे मातरम् के गायन में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और माफ़ी मांगने को कहा। यही नहीं, दिल्ली पुलिस से जाँच करने और रिपोर्ट देने को भी कहा है।

विवरण देते हुए पूछा कि सभी पक्षों को संतुष्ट रखने और हिंदू-मुस्लिम टकराव को और बढ़ने से रोकने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाना चाहिए। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी और कई अन्य नेता मौजूद थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर से भी दोबारा सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि जिस

तीसरे अंतरे को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उसे हटा दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि जब भारत स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है, तब सभी विवादाल्पद मुद्दों को अलग रख देना चाहिए। टैगोर ने बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय से भी बात की। बंकिम चन्द्र ने कहा कि उन्हें किसी भी अंतरे को हटाय जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद मामला सुलझा लिया गया और विवाद समाप्त हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला किया कि मुसलमानों को लगातार उकसाते रहना जरूरी है, ताकि हिंदू-मुस्लिम विभाजन पहले से कहीं अधिक गहरा हो सके। मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत पूरा वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया गया और इसे न गाने पर सजा का प्रावधान किया गया। 15 अगस्त को कांग्रेस ने अपने नए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक है।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचैतक जोगेश्वर गर्ग, मुख्य सचैतक प्रतिपक्ष रफीक खान सहित, विभिन्न दलों के विधायकों को आमंत्रित किया गया है। देवनानी ने कहा कि विधानसभा जनहित के मुद्दों पर चर्चा का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच है। सदन की गरिमा बनाए रखना सत्ता पक्ष और विपक्ष सहित, सभी विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों के बीच संवाद, समन्वय और विश्वास का वातावरण तैयार होता है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में जनमहत्व के विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सकारात्मक वातावरण जरूरी है। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सदन की कार्यवाही को सुव्यवस्थित, गरिमापूर्ण और जनहित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भाजपा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधामोहन लाल अग्रवाल तथा राष्ट्रीय सचिव सांसद अलका गुर्जर को स्थान नहीं मिला।

संगठन में लंबे अनुभव के साथ सक्रिय रहे हैं। जून 2026 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने से उनका राजनीतिक दायरा प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। पुनिया को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद आने वाले समय में चुनावी रणनीति, संगठन विस्तार और पार्टी के महत्वपूर्ण अभियानों में उनकी भूमिका बढ़ सकती है। दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखना उनके राजनीतिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे पुनिया

लेकर पार्टी के भरोसे का संकेत माना जा रहा है। राजे इससे पहले जेपी नड्डा की राष्ट्रीय टीम में भी उपाध्यक्ष थीं। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को भाजपा एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से यह नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजस्थान सहित, आदिवासी बहुल राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने में रावत की भूमिका अहम हो सकती है। राजस्थान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश मंगल को पीपूष गोयल के साथ राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इन नियुक्तियों के जरिए राजस्थान के संगठनात्मक अनुभव वाले नेताओं को केन्द्रीय संगठन में जगह दी गई है। नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल को स्थान नहीं मिला है। राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बना सकीं। इसके बजाय राजेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या देवेन्द्र फड़नवीस दिल्ली शिफ्ट होंगे?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फड़नवीस की प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर राजनैतिक हलकों में यह सवाल पूछा जा रहा है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के सोमवार को नई दिल्ली दौरे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी मुलाकात ने एक बार फिर उन्हें केन्द्र सरकार में लिए जाने की संभावना को लेकर राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। फडणवीस ने प्रधानमंत्री को राज्य की प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इनमें राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो विस्तार और नदी जोड़ो परियोजनाएँ शामिल हैं। उन्होंने केन्द्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं के लिए केन्द्र से और अधिक सहयोग की भी मांग की। हालाँकि, बाद में उन्होंने दिल्ली

- फड़नवीस का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल का प्रशासनिक अनुभव है, वे युवा हैं और उनकी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी है, यही नहीं, अक्सर प्रधानमंत्री के पद पर मोदी के विकल्प के रूप में उनका नाम लिया जाता है, हालांकि, खुद फड़नवीस इससे इंकार कर चुके हैं।
- चर्चा है कि अगर फड़नवीस केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो उन्हें संभवतया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है।
- फड़नवीस ने कहा कि उनकी प्र.मंत्री मोदी से मुलाकात राज्य की योजनाओं के संदर्भ में थी, वे दिल्ली शिफ्ट नहीं हो रहे हैं और महाराष्ट्र में ही बने रहेंगे।

आने की अटकलों को खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत में फड़णवीस ने कहा कि जो लोग ऐसी अटकलों के “गुब्बारे” या “पतंगें” उड़ा रहे हैं, वे

कतर में रहने वाले भारतीय यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। कतर में रहने वाले भारतीय अब डाकघरों के माध्यम से भारत में यूपीआई से जुड़े बैंक खातों में सीधे पैसे भेज सकेंगे। कतर-भारत धन प्रेषण (पोस्टल रैमिटेंस)

- यह सेवा डाक विभाग तथा कतर डाक सहित संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है।

सेवा 15 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सुविधा डाक विभाग और कतर डाक सहित, अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है। केन्द्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि इस सेवा के तहत कतर में ग्राहक कतर के डाकघर जाकर भारत में किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

“दिमागी नक्सल” कौन होता है? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्र.मंत्री मोदी की “दिमागी नक्सल” टिप्पणी ने नई राजनैतिक बहस छेड़ दी है

- प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कई योजनाएँ घोषित कीं, साथ ही यह भी कहा कि युवाओं के एक वर्ग का “दिमागी नक्सली” लोगों द्वारा “ब्रेन वॉश” किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है।
- विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्र.मंत्री का इशारा स्वतंत्र विचारधारा और वामपंथी रुझान वाले छात्र संगठनों की ओर है और उनकी दिमागी नक्सल टिप्पणी सरकार की भावी दिशा का संकेत दे रही है।

है, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली या स्वतंत्र विचारधारा की छात्र राजनीति शक की नजर से देखी जाती है। “दिमागी नक्सल” का तंत्र इस बात का संकेत भी है कि आने वाले महीनों में छात्र राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। सभी संकेतों से लगता है कि एबीवीपी के लिए यह काफी सक्रिय दौर होने वाला है। परिसरों में अपनी पहुंच बढ़ाने, जवाबी लामबंदी करने और अपने विरोधियों को राष्-

की यह दोहरी रणनीति सीजेपी के बाद की जैनेरेशन ज़ी की उभरती मुखरता को नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, यह अभी एक खुला राजनीतिक सवाल है। कॉंकरोच जनता पार्टी के जैनेरेशन ज़ैड आंदोलन, जिसने पेपर लोक के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था, उससे जुड़े छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री के भाषण को इस बात के एक और प्रमाण के रूप में लिया है कि सरकार युवाओं के गुस्से को समझने और उसके मुलौ कारणों को दूर करने के बजाय उसे किसी लेबल से जोड़ने में अधिक सहज है। सीजेपी और वामपंथी छात्र संगठनों को पहले ही अर्बन नक्सल जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा है। अब इस्तेमाल किया गया नया शब्द उस रणनीति के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जिसे ऐसी पीढ़ी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अगर एयरलाइन किराया बढ़ाये तो केन्द्र उड़ानें रोके’

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। उच्चतम न्यायालय ने त्योंहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

- सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को सख्त निर्देश दिये।

अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यात्रियों के हित में व्यवस्था तो बनाई गई है, लेकिन उसके पालन और नियमन को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर एयरलाइंस कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, तो उनकी उड़ानें रोकने तक के कदमों पर विचार किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की

इलायची और माउथ फ्रैशनर के बहाने पान मसाला ब्रांड का प्रचार, कानून से खिलवाड़ की एक और मिसाल

महाराष्ट्र सरकार ने विमल इलायची के प्रचार के लिए बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ एक्शन लेकर “सरोगेट एडवर्टिज़मेंट” के खेल को सुखियों में ला दिया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 अगस्ता। विमल इलायची के विज्ञापनों को लेकर बॉलीवुड स्टार शाहरूख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई ने भारत की सरोगेट विज्ञापन (छद्म विज्ञापन) के खिलाफ लंबे समय से चल रही लड़ाई को फिर से चर्चा में ला दिया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल खड़ा करता है: किसी ऐसे उत्पाद का विज्ञापन, जो देखने में पूरी तरह वैध है, कब प्रतिबंधित तंबाकू या पान मसाला उत्पाद का अप्रत्यक्ष विज्ञापन बन जाता है?

- “सरोगेट” यानि छद्म विज्ञापन वे विज्ञापन हैं, जिनमें किसी प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी अन्य प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है, जैसे विमल गुटखा के प्रचार के लिए विमल इलायची का विज्ञापन किया जाता है।
- भारत में तंबाकू आधारित उत्पादों के विज्ञापन पर कानून रोक है और इस कानून में बाद में ऐसे नियम भी जोड़ दिए गए, जिनमें तंबाकू उत्पाद ब्रांड के प्रचार के लिए अन्य उत्पाद का प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
- उपभोक्ता संरक्षण कानून की गाइडलाइन्स में भी “सरोगेट” विज्ञापन पर रोक लगाई गई है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिल्मी हस्तियों पर की गई कार्यवाही सैलिब्रिटी विवाद बन कर न रह जाए, यह ध्यान रखना होगा, क्योंकि, यह मुद्दा इस विवाद का समाधान कर सकता है कि क्या किसी वैध उत्पाद की आड़ में प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है।

वाली कंपनियाँ इलायची, माउथ फ्रेशनर और अन्य उत्पादों जैसे ब्रांड एक्सटेंशन के जरिए, अपने ब्रांड को लोगों की नजर में बनाए रखती हैं, जबकि उक्त उत्पादों के सीधे विज्ञापन पर प्रतिबंध है। भारत में इस तरह की गतिविधियों से निपटने के लिए पहले से ही एक

मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सी.ओ.पी.टी.ए.), 2003 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाता है।

सेवाओं या कार्यक्रमों के प्रचार के लिए करना भी शामिल है। उपभोक्ता संरक्षण कानून की व्यवस्था भी इसमें एक और स्तर जोड़ती है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की 2022 की गाइडलाइंस उन वस्तुओं और सेवाओं के सरोगेट या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर रोक लगाती हैं, जिनके विज्ञापन पर पहले से प्रतिबंध या रोक है। फिर भी इन नियमों को लागू करना मुश्किल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का बचाव (डिफेंस) सीधा है: विज्ञापन पूरी तरह से वैध उत्पाद के लिए है। इस बचाव की अदालतों में परीक्षा हो चुकी है। विमल इलायची से जुड़े एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- उन्होंने भाजपा व शीर्ष नेतृत्व को मार्ग दर्शन व सहयोग के लिये आभार व्यक्त किया।

कर लिया जाए। इससे पहले भी उन्होंने 30 जुलाई को इस्तीफा दिया था, लेकिन पार्टी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। सोमवार को भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपना इस्तीफा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भेजा है और इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकारश्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्रीजल प्रबंधन में नए कीर्तिमान
जल समृद्ध हो रहा राजस्थान₹91,000 करोड़ की लागत से
राम जल सेतु लिंक परियोजना

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- 4.98 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा
- 17 जिलों को पेयजल- जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, डीग कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, धौलपुर

₹34,102 करोड़ की
यमुना जल परियोजना

शेखावाटी को वर्षों बाद जल

32 वर्षों का इंतजार पूरा

चूरु, सीकर, झुंझुनू - भरपूर पानी



राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर

गंग, भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी-तंत्र के जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण के लिए राशि ₹5500 करोड़

लाभान्वित जिले - हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरू, बीकानेर, फलौदी

जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, डीडवाना- कुचामन, बाड़मेर और बालोतरा

ब्राह्मणी-राणा प्रताप सागर- बनास लिंक

680 एमसीएम जल बनास नदी में अपवर्तन लाभान्वित जिले भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर एवं डीग

₹2,500 करोड़

की अपर हाई लेवल कैनाल माही परियोजना से बांसवाड़ा के 338 गांवों में सिंचाई

देवास तृतीय एवं चतुर्थ बांध का निर्माण

राज्य सरकार द्वारा राजसमंद जिले में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु खारी फीडर की जल संवहन क्षमता को दोगुना करने की लगभग ₹150 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना

₹7,355 करोड़ की

परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से कोटा, बारां, झालावाड़ के 571 गांवों में 2.01 लाख हेक्टेयर सिंचाई एवं 1402 गांवों में पेयजल सुविधा

पाली एवं सिरोही में पेयजल आपूर्ति हेतु सेई एवं साबरमती बांधों का निर्माण कर जवाई बांध में पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना लागत ₹1,255.90 करोड़ है साथ ही, सेई बांध की टनल क्षमता बढ़ाने पर ₹65 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

माही बेसिन के अनास एवं सोम नदियों के 500 MCM अधिशेष जल को जाखम बांध, जयसमंद बांध के साथ साथ सोम-कमला-अंबा बांध के माध्यम से जवाई बांध एवं जालौर तक आपवर्तित करने का संकल्प लाभान्वित जिले: बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालौर एवं जोधपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल के महत्वपूर्ण जल समझौतों से विकास की गंगा बहेगी- शिवराज सिंह चौहान

केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा मुख्यमंत्री ने बारां व झालावाड़ में 1258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

बारां/जयपुर, 17 अगस्त। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हुए पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना समझौते से 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, यमुना जल से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में निरंतर विकास की गंगा बहेगी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बारां, झालावाड़, कोटा के कृषि क्षेत्र में विकास का रोडमैप बनाया जाएगा। इससे किसान नई फसलों की पैदावार कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राजस्थान के लिए 3 हजार 473 करोड़ रुपये की लागत से 2 लाख 89 हजार 355 नवीन आवास निर्माण तथा कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि उन्नत योजना के लिए 340 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति के पत्र सौंपे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने,



केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारां की कृषि उपज मंडी में बारां-झालावाड़ के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

कृषि लागत कम करने और उन्हें आसान ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बारां एवं झालावाड़ जिलों में 1 हजार 258 करोड़ के 98 विकास कार्यों का

शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले ढाई साल में बारां के समग्र विकास के लिए 3 हजार 316 करोड़

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पीएम-कुसुम तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने किसानों की आय को सुरक्षित करने व कृषि लागत कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एवं झालावाड़ के लिए 6 हजार 474 करोड़ सहित कुल 10 हजार करोड़ से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा स्थल पर बारां जिला प्रशासन की विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनों का अवलोकन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा, राधेश्याम बैरवा, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण सहित, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

नितिन नबीन ... आईएसआई के शहज़ाद भट्टी नेटवर्क के 255 संदिग्ध गिरफ्तार

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राजस्थान के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारियों के बाद प्रदेश की राजनीति में भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बनाए रखा गया है, तो दूसरी ओर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर संगठन में उनका कद बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा की सरकार है। ऐसे में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय संगठन में मौजूदगी आने वाले समय में केन्द्र और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नई नियुक्तियों से एक बात साफ है कि भाजपा ने राजस्थान के अनुभवी, संगठनात्मक और सामाजिक आधार वाले नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर प्रदेश को संगठन की नई रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब इन नियुक्तियों का असर राजस्थान भाजपा के भीतर आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक समीकरणों पर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

नई दिल्ली, 17 अगस्ता। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों में 253 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास एसबीएन से जुड़ी संभावित अटकलों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि मोदी ही पार्टी के नेता हैं और 2029 में भी वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

समर्थित आतंकी समूह 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' को खत्म कर दिया और 200 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। शाह ने कहा कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस समूह के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

शहजाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूनावाला ने भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीएल संतोष से उन्हें लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला।

उन्होंने कहा कि भाजपा और व्यापक संघ परिवार ने उन्हें जो अवसर और मंच प्रदान किया, उसके लिए वे सदैव कृतज्ञ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक युवा, पसमांदा मुस्लिम और गैर-वंशवादी व्यक्ति को भाजपा ने अवसर प्रदान किया। पूनावाला ने कहा कि वे उस पार्टी और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद को अलविदा कह रहे हैं, जिसे वे बेहद पसंद करते हैं।

क्या देवेन्द्र फड़नवीस दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। इनमें तीन बार मुख्यमंत्री के रूप में उनका मजबूत प्रदर्शन, नागपुर से उनका संबंध और आरएसएस से उनके करीबी रिश्ते प्रमुख हैं। इसके अलावा, विपक्षी नेताओं की ओर भी से बार-बार यह दावा किया जाता रहा है कि उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, तथा शिखा जैसे किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की समय-समय पर होने वाली चर्चाओं और केन्द्र में अनुभवी प्रशासकों की भाजपा की जरूरत ने भी इन अटकलों को लगातार हवा दी है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के साथ फड़णवीस की मुलाकात ने उनके राष्ट्रीय स्तर पर संभावित भविष्य को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं को फिर से जीवित कर दिया है।

पिछले कुछ वर्षों में भाजपा और आरएसएस के हलकों में उन्हें कभी-कभार भविष्य के संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी देखा गया है। इसके पीछे उनका प्रशासनिक अनुभव, अपेक्षाकृत कम उम्र और संघ परिवार में उनकी मजबूत जड़ें बताई जाती हैं।

कुछ राजनीतिक विश्लेषणों में यह भी कहा गया है कि उन्हें मोदी के उनका कहना रहा है कि मोदी ही पार्टी के नेता हैं और 2029 में भी वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

आरएसएस के दबाव में निकट भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन के दावे फिलहाल वास्तविकता पर आधारित होने के बजाय, विपक्ष की ओर से पैदा की गई राजनीतिक अटकलें अधिक

वंदे मातरम् का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्यालय इंदिरा भवन में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया।

पहले दो अंतरे गाए जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा कि गीत गाया जा चुका है और इतना पर्याप्त है। सोनिया गांधी ने इसके बाद राहुल गांधी से कहा कि खड़गे जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनो।

राहुल गांधी ने उन्हें समझाया कि कांग्रेस के कुछ लोगों को पूरा वंदे मातरम् गाने पर आपत्ति है और ध्वजारोहण से पहले इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई थी।

इसके बाद तय किया गया कि चूंकि अब इसे कानून का रूप दे दिया गया है, इसलिए पूरा गीत गाया जाएगा।

और इंदिरा भवन में ठीक यही हुआ।

इससे पहले सोनिया गांधी को इशारे करते हुए देखा गया कि वे कुछ कैमरा संचालकों से वहां से हटने और कार्यक्रम की कार्यवाही में बाधा न

इलायची और माउथ फ्रेशनर के बहाने ...

डालने के लिए कह रही थीं।

मामला यहीं समाप्त हो गया। लेकिन अमित शाह ने इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक विवाद बना दिया है। वे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर वंदे मातरम् को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं और इसके लिए माफी मांगने की बात कर रहे हैं।

वे केवल माफी ही नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूरे घटनाक्रम की जांच करने और यह रिपोर्ट देने को भी कहा है कि क्या कानून का उल्लंघन हुआ है। एक बेहद खूबसूरत देशभक्ति गीत को नफरत और दुश्मनी की राजनीति में घसीटकर भाजपा द्वारा हिंदू बनाम मुस्लिम विभाजन की आग को जलाए रखने और उससे अधिकतम राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

वंदे मातरम् की शुरुआत कांग्रेस के साथ हुई थी और अब भाजपा इस आग को जलाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, ताकि इससे अधिकतम राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रों की मांग मानी, परीक्षा रद्द की

- मुख्यमंत्री सोरेन की घोषणा पर आंदोलनरत छात्रों ने खुशी जताई, पर सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की
- मुख्यमंत्री सोरेन ने लखनऊ की डेटा प्रोसेसिंग और परीक्षा करवाने वाली संस्था टीएसआर डेटा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व भर्तियों को रद्द करने की घोषणा की।

छात्र नेता देवेन्द्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फैसले के लिए बधाई दी और इसे छात्रों के आंदोलन की बड़ी सफलता बताया। हालांकि, आंदोलन कर रहे कुछ छात्रों का कहना है कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मांगें मान ली गई हैं, लेकिन उनका आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्रों ने कहा कि परीक्षाएं और भर्तियां रद्द करने की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

छात्रों की प्रमुख मांग अब पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार सीबीआई जांच कराने पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षाएं रद्द करने से पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आएगी। दावाियों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र जांच जरूरी है।

C
M
Y
K

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम घोषित की

राममाधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त, पीयूष गोयल कोषाध्यक्ष बने

- नई टीम में महिलाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी गई है तथा संगठनात्मक अनुभव, युवा ऊर्जा व क्षेत्रीय संतुलन पर ध्यान दिया गया है।

पुंरदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रती सिंह बादल, लाल सिंह अग्र, एम. नागराज, तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) होंगे। शिव प्रकाश और सौदान सिंह को फिर राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी दी गयी है। विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेन्द्र पटेल, हरिश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महासचिव होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। चार महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

रामायण देव, स्मृति ईरानी, सतीश पूनिया, गजेन्द्र पटेल, हरिश द्विवेदी, संजय भाटिया राष्ट्रीय महासचिव होंगे। पीयूष गोयल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी ने कुल 7 राज्यों से 8 महामंत्री बनाए हैं और सबसे ज्यादा दो नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं। चार महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है।

+